'लखपति दीदी' एक अनूठी पहल

-सरला मीणा

'लखपति दीदी' पहल का उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वरोज़गार और कौशलयुक्त रोज़गार के अवसर प्रदान करना है। यह योजना महिलाओं को आवश्यक कौशल से लैस करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए तैयार की गई है जो सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करती है। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं के लिए टिकाऊ और विविध आजीविका विकल्प तैयार करना है, जिससे ज़मीनी स्तर पर गरीबी कम कर आर्थिक सशक्तीकरण में योगदान दिया जा सके।

आज 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों का हिस्सा हैं। जब आप किसी गाँव में जाते हैं, तो आपको 'बैंक वाली दीदी', 'आंगनबाड़ी दीदी' और 'दवाई वाली दीदी' मिलेंगी। "गाँवों में दो करोड़ लखपति दीदी बनाना मेरा सपना है"- 15 अगस्त, 2023 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में लाल किले की प्राचीर से इन शब्दों के साथ, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश भर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहल 'लखपति दीदी' योजना का अनावरण किया।

'लखपति दीदी' योजना का उद्देश्य दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत आने वाले 10 करोड़ स्वयं सहायता समूहों के बड़े परिवार की कम-से-कम दो करोड़ दीदियों को जल्दी से जल्दी सक्षम बनाना है।

एसएचजी या स्वयं सहायता समूह समुदाय-आधारित संगठन होते हैं जो व्यक्तियों के समूह, मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा गठित होते हैं जो अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक या विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक साथ आती हैं। महिला स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सशक्त बनाने, सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और ज़मीनी स्तर पर शासन में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और 'लखपति दीदी' वह हैं जो प्रति परिवार कम से कम एक लाख रुपये प्रति वर्ष की सतत आय अर्जित करती हैं। अमृतकाल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और परिदृश्य को 'लखपति दीदी' चलाने जा रही हैं।

लेखिका पत्र सूचना कार्यालय में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

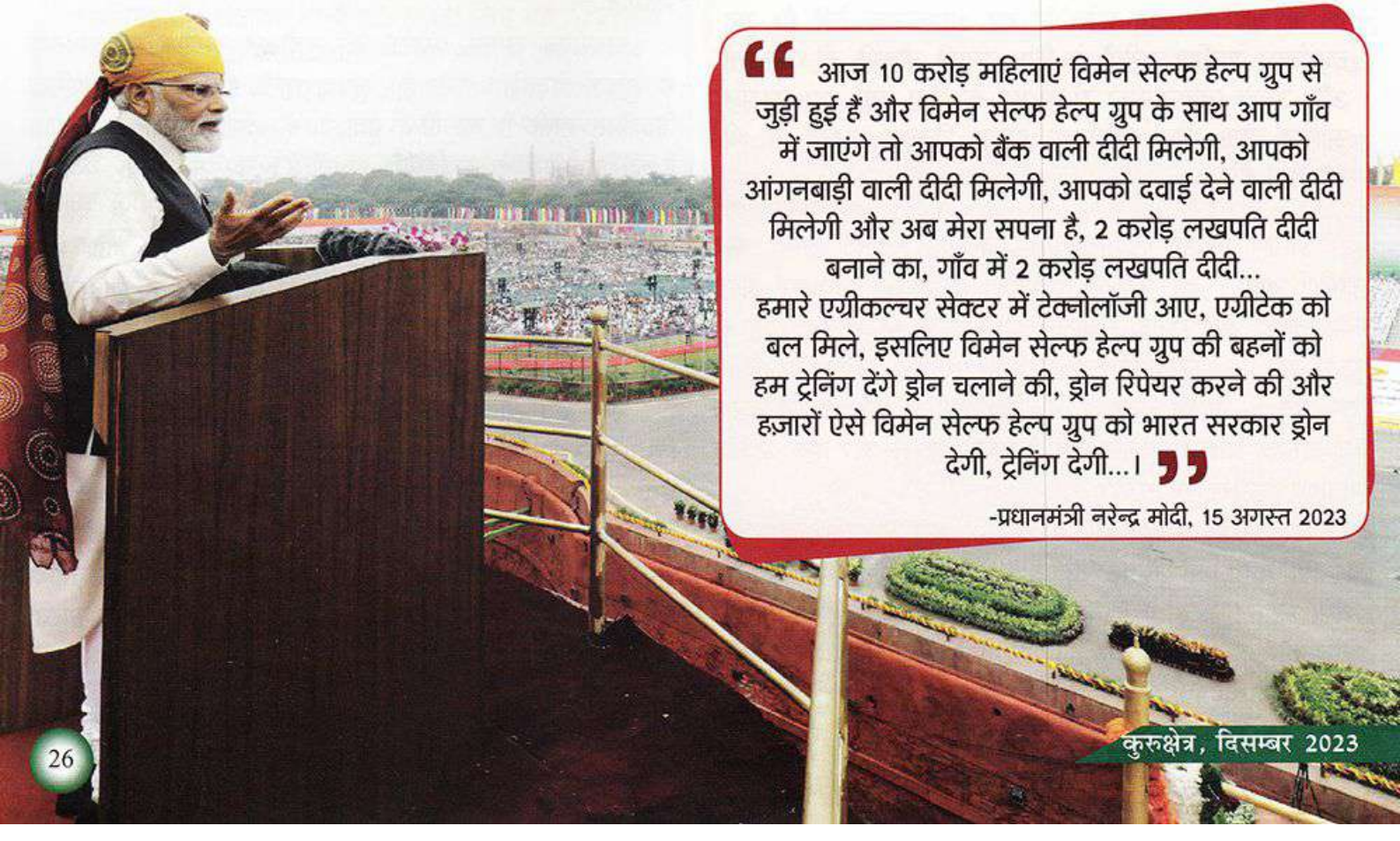

> "आज 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गाँव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनबाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी और अब मेरा सपना है, 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गाँव में 2 करोड़ लखपति दीदी...
> हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयर करने की और हज़ारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी...।"
>
> -प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, 15 अगस्त 2023

"इस योजना के तहत, महिलाओं को उभरते उद्योगों की मांगों के अनुरूप, कई व्यावहारिक कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन कौशलों में नलसाज़ी (पलंबिंग), एलईडी बल्ब निर्माण और ड्रोन के संचालन और मरम्मत आदि कार्य शामिल हैं। 'लखपति दीदी' योजना 'स्टेम' (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) में भी महिलाओं को सशक्त बना रही है।"

प्रधानमंत्री ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के महत्व को रेखांकित किया है और बताया है कि देश को आगे ले जाने के लिए यह कितना ज़रूरी है। आज भारत में 'स्टेम'* में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है और दुनिया आज भारत की इस क्षमता को देख रही है। उपरोक्त वर्णित विविध प्रशिक्षण दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करते हैं कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर सकें और उद्यमिता के अवसरों का पता लगा सकें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, कड़ी मेहनत और बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ, समयबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित और तत्पर है। मंत्रालय ने अब तक 1.5 करोड़ से अधिक लखपति दीदियों को सफलतापूर्वक सक्षम किया है और 2 करोड़ के लक्ष्य को मार्च 2024 के बजाय इस वर्ष के अंत तक पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय इस लक्ष्य को पाने के लिए कई कदम उठा रहा है और इसमें सरकारी विभागों और एजेंसियों को शामिल कर रहा है ताकि 'लखपति दीदी' पहल से ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं लाभान्वित हो सकें। इस दृष्टिकोण के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूपांतरण के लिए अभिसरण (कन्वर्जन्स) से इस पहल की सफलता को सुनिश्चित करना शामिल है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत ग्रामीण गरीब युवाओं और महिलाओं को 'आयुष' स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर, कुशल कर्मी तैयार करने में सहयोग हेतु आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

'लखपति दीदी' पहल का कार्यान्वयन दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के दायरे में आता है। यह योजना भारत सरकार का एक प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और आज यह ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहल है। गरीबी के कई आयामों को संबोधित करते हुए, कार्यक्रम का लक्ष्य 10 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुँचना और प्रत्येक

*STEM-Science,Technology, Engineering, Mathematics

ग्रामीण परिवार से एक महिला सदस्य को आत्मीयता-आधारित महिला स्वयं सहायता समूह में संगठित करना है। ये स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को निकट, दीर्घकालिक सहायता प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें बैंकों की वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने, अपनी आजीविका में विविधता लाने और उसे सतत जारी रखने के साथ-साथ आसानी से एवं प्रभावी ढंग से अपने अधिकारों तक पहुँचने में मदद मिलती है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार, 6-8 वर्षों तक स्वयं सहायता समूह में रहने के बाद, घरेलू खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो और उसके पास एक से अधिक सतत आजीविका स्रोत हों।

मिशन ने, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने प्रयास में, महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए उनके सामूहिकीकरण, उनके संघों को मज़बूत बनाने, उन्हें ज्ञान और कौशल के साथ सक्षम बनाने तथा वित्तपोषण और ऋण सहायता आदि जैसे कुछ ठोस प्रयास किए हैं।

मिशन चार मुख्य घटकों में निवेश के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत है-

(क) सामाजिक लामबंदी और ग्रामीण गरीबों के स्व-प्रबंधित और वित्तीय रूप से टिकाऊ सामुदायिक संस्थानों को बढ़ावा देना और मज़बूत करना;

(ख) ग्रामीण गरीबों का वित्तीय समावेशन;

(ग) सतत आजीविका; और

(घ) सामाजिक समावेशन, सामाजिक विकास और अभिसरण।

मिशन की प्रगति

1. **भौगोलिक कवरेज** : मिशन ने प्रखर रणनीति के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) के 742 ज़िलों में फैले 7091 ब्लॉकों को कवर किया है।

2. **सामाजिक लामबंदी/संस्थागत निर्माण** : 9.54 करोड़ महिलाओं को 87.39 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया गया है।

3. **सामाजिक पूंजी** : समुदाय संचालित दृष्टिकोण मिशन की कार्यान्वयन रणनीति का केंद्र है। लगभग 4 लाख सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को कई हस्तक्षेपों में प्रशिक्षित किया गया है।

4. **पूंजीगत समर्थन** : संचयी रूप से, मिशन के तहत सामुदायिक निवेश सहायता के रूप में लगभग 33,497.62 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

5. **एसएचजी-बैंक लिंकेज** : वर्ष 2013-14 से स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगभग 6.96 लाख करोड़ रुपये का बैंक ऋण प्राप्त किया गया है। 1.88% पर एनपीए, मिशन के विभिन्न स्तरों पर किए गए प्रयासों का परिणाम है।

6. **बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट (बीसीए) के रूप में एसएचजी सदस्य** : वित्तीय सेवाओं को उपभोक्ताओं के द्वार तक पहुँचाने के लिए एक लाख से अधिक एसएचजी सदस्यों को बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट/डिजीपे (Digipay) पॉइंट के रूप में पहचाना और प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान में, 1.07 लाख बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी/डिजीपे सखियों को तैनात किया जा चुका है।

> "जब महिलाएं समृद्ध होती हैं, तो दुनिया समृद्ध होती है। उनका आर्थिक सशक्तीकरण विकास को बढ़ावा देता है और शिक्षा तक उनकी पहुँच वैश्विक प्रगति को गति देती है। उनका नेतृत्व समावेशिता को बढ़ावा देता है और उनकी आवाज़ सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करती है। महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका महिला-नेतृत्व वाला विकास दृष्टिकोण है और भारत इस दिशा में तेज़ी से प्रगति कर रहा है।"

7. **आजीविका** : डीएवाई-एनआरएलएम फार्म हस्तक्षेपों के तहत गहन ब्लॉकों में सतत कृषि, पशुधन और एनटीएफपी को बढ़ावा देता है। हस्तक्षेपों का फोकस फसल और पशुधन उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और कृषि पारिस्थितिकी प्रथाओं को बढ़ावा देने पर है। 23 अगस्त, 2023 तक, 3.02 करोड़ महिला किसानों को इन हस्तक्षेपों के तहत कवर किया जा चुका है। गैर-कृषि रणनीति के तहत, डीएवाई-एनआरएलएम स्टार्टअप विलेज एंत्रप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी)* पर काम करता है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों को स्थानीय उद्यम स्थापित करने में सहायता करना

है। वर्ष 2016-17 से लागू, एसवीईपी के तहत अब तक लगभग 2.45 लाख उद्यमों को मदद दी जा चुकी है।

8. **कस्टम हायरिंग सेंटर/टूल बैंक** : कई राज्यों में लगभग 28623 कस्टम हायरिंग सेंटर/सामुदायिक प्रबंधित टूल बैंक स्थापित किए गए हैं। ये सीएचसी छोटे और सीमांत किसानों को मामूली दर पर कृषि उपकरण और अन्य सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं।

मिशन के तहत, लगभग 9.54 करोड़ महिलाएं 87.39 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का हिस्सा हैं। वित्तीय समावेशन में काफी प्रगति हुई है, उदाहरण के लिए वित्तीय साक्षरता, बैंक खाते खोलना, ऋण, बीमा आदि। एसएचजी को लगभग ₹ 33,497 करोड़ की पूंजीगत सहायता प्रदान की गई है। इससे वर्ष 2013-14 से एसएचजी और उनके संघों को बैंकों से ₹ 6.95 लाख करोड़ का क्रेडिट लिंकेज संभव हो सका है।

मिशन ने संपूर्ण समाज दृष्टिकोण को अपनाया है जहां एसएचजी परिवारों की आय बढ़ाने हेतु सभी ज़रूरी मदद देने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, बहुपक्षीय एजेंसियों, सीएसओ और तकनीकी संस्थानों के साथ सहयोग और साझेदारी मज़बूत हुई है। मिशन ने बड़ी संख्या में सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को तैयार किया है, जो एनआरएलएम के तहत ज़मीन से जुड़े हैं और मिशन द्वारा किए गए हस्तक्षेपों को सुविधाजनक बनाने में सहायक हैं।

वर्तमान में मिशन द्वारा पांच लाख से अधिक सीआरपी (समूह सखी, कृषि सखी, पशु सखी, मधु सखी, मत्स्य सखी, बैंक सखी, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी आदि सहित) नियुक्त किए जा चुके हैं। ये सीआरपी आजीविका हस्तक्षेपों, विभिन्न विस्तार सेवाओं आदि की तकनीकी जानकारी में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। इसके अलावा, मिशन ने हितधारकों की मदद और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए राज्य, ज़िला और उप ज़िला-स्तर पर पेशेवरों (राष्ट्रीय संसाधन व्यक्तियों और राज्य संसाधन व्यक्तियों) को भी नियुक्त किया है।

इसी प्रकार, महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को गति देने के लिए, 'लखपति दीदी' पहल की शुरुआत दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा की गई है, जिसमें प्रत्येक एसएचजी परिवार को मूल्य शृंखला हस्तक्षेपों के साथ मिलकर कई आजीविका गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, परिणामस्वरूप प्रति वर्ष एक लाख रुपये या उससे अधिक की स्थायी आय हो सके। 'लखपति दीदी' पहल और डीएवाई-एनआरएलएम ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

'लखपति दीदी' पहल का उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वरोज़गार और कौशलयुक्त रोज़गार के अवसर प्रदान करना है। यह योजना महिलाओं को आवश्यक कौशल से लैस करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए तैयार की गई है जो सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करती है। ये पहल ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और अधिकारों तक उनकी पहुँच बढ़ाने के लिए सामाजिक लामबंदी, वित्तीय समावेशन, सतत आजीविका और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इन प्रयासों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं के लिए टिकाऊ और विविध आजीविका विकल्प तैयार करना है, जिससे ज़मीनी स्तर पर गरीबी कम कर आर्थिक सशक्तीकरण में योगदान दिया जा सके।

संक्षेप में, ये कहावत सौ फीसदी सही है कि जब महिलाएं समृद्ध होती हैं, तो दुनिया समृद्ध होती है। उनका आर्थिक सशक्तीकरण विकास को बढ़ावा देता है और शिक्षा तक उनकी पहुँच वैश्विक प्रगति को गति देती है। उनका नेतृत्व समावेशिता को बढ़ावा देता है और उनकी आवाज़ सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करती है। महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका महिला-नेतृत्व वाला विकास दृष्टिकोण है और भारत इस दिशा में तेज़ी से प्रगति कर रहा है। ❑